सांध्य दैनिक
4PM
जिद...सच की
www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_SanjayS YouTube @4pm NEWS NETWORK
● वर्ष: 12 ● अंक: 50 पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, गुरुवार 26 मार्च, 2026
मूल्य ₹ 3/-

अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और तुरंत इसे क्रियान्वित करने की शुरुआत कर दें, चाहे आप तैयार हों या नहीं।
-नेपोलियन हिल

गायकवाड़ के साथ संजू सैमसन... 7 | विधेयकों को पास करवाने में नहीं... 3 | भाजपा सरकार सपा कार्यकर्ताओं... 2

बंगाल की सियासत में बवाल

ममता का सीधा वार, अब निशाने पर चुनाव आयोग के साथ सुरक्षा बल

» लोकतंत्र की रक्षा या सत्ता की साजिश?
» क्या बंगाल में निष्पक्ष चुनाव सिर्फ एक भ्रम बनकर रह गया है?
» ममता का बिगुल अब चुप नहीं बैठेंगे
» एक दिन के लिए बूथ बचा लो पांच साल शांति मिलेगी

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। लोकतंत्र अब यह शब्द किताबों में जितना पवित्र दिखता है जमीन पर उतना ही संदिग्ध होता जा रहा है। और पश्चिम बंगाल में तो मानो लोकतंत्र अब बैलेट से नहीं बल्कि बैलेट को कंट्रोल करने वाली ताकतों से तय हो रहा है।

सीएम ममता बनर्जी ने इस बार कोई हल्का आरोप नहीं लगाया है उन्होंने चुनाव आयोग के बाद पश्चिम बंगाल चुनाव को निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी निभाने पहुंचे सशस्त्र सुरक्षा बलों पर गंभीर आरोप लगाये हैं। उनके आरोप बताते हैं कि मामला कितना गहरा और कितना खतरनाक हो चुका है।

ममता की कठिन हो गई राह

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की राजनीति कभी आसान नहीं रही। वह उन नेताओं में से हैं जिन्होंने सत्ता विरासत में नहीं पाई बल्कि सड़कों पर संघर्ष कर के हासिल की। कांग्रेस से निकलकर अपनी पार्टी बनाना वामपंथ के 34 साल के किले को ढहाना यह सब किसी साधारण नेता के बस की बात नहीं थी। लेकिन सत्ता में आने के बाद उनकी राह और कठिन हो गई। एक तरफ केंद्र की भाजपा सरकार दूसरी तरफ राज्य की जमीनी चुनौतियां ममता हमेशा दो मोर्चों पर लड़ती नजर आईं। बीजेपी का बंगाल में उभार उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बना। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही बंगाल की राजनीति में ध्रुवीकरण तेज हुआ। हिंसा, आरोप प्रत्यारोप, और एजेंसियों की एंट्री सब कुछ तेजी से बदलने लगा। ममता के लिए सबसे बड़ा संकट यह रहा कि उन्हें सिर्फ विपक्ष से नहीं बल्कि सिस्टम से भी लड़ना पड़ा। सीबीआई, ईडी, और अब चुनाव आयोग हर मोर्चे पर उन्होंने खुद को घिरा हुआ पाया। उनके कई करीबी नेताओं पर कार्रवाई हुई। पार्टी के भीतर भी असंतोष के सुर उठे। लेकिन इसके बावजूद ममता ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी छवि एक लड़ाकू नेता की बनाई जो झुकती नहीं टकराती है।

"यह शर्म की बात है कि पश्चिम बंगाल के नागरिकों को इतने सालों बाद अब अपनी नागरिकता का सबूत देने के लिए मजबूर किया जा रहा है।"

"केंद्रीय बल भी कमीशन की तरह ही पश्चिम बंगाल में भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है।"

ममता की लड़ाई बंगाल की नहीं बल्कि विचार की

आज जब देश की राजनीति में बड़े-बड़े चेहरे सत्ता के सामने झुकते नजर आते हैं, ममता बनर्जी एक अलग तस्वीर पेश करती हैं। वह सवाल पूछती हैं टकराती हैं और सबसे बड़ी बात डरती नहीं हैं। उनके आरोपों को सिर्फ राजनीति कहकर खारिज करना आसान है लेकिन उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज करना खतरनाक भी हो सकता है। क्योंकि अगर एक चुनी हुई मुख्यमंत्री बार बार सिस्टम पर सवाल उठा रही है तो कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ममता की लड़ाई सिर्फ बंगाल की नहीं बल्कि उस विचार की है जिसमें राज्यों की स्वायत्तता, लोकतंत्र की निष्पक्षता और जनता का अधिकार शामिल है। उनका यह कहना कि एक दिन के लिए बूथ बचा लो पांच साल शांति मिलेगी यह सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि लोकतंत्र का सार है। बंगाल आज एक प्रयोगशाला बन चुका है जहां यह तय होगा कि लोकतंत्र कितना मजबूत है और संस्थाएं कितनी निष्पक्ष। और इस जंग में ममता बनर्जी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक योद्धा हैं जो आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार है। अगर लोकतंत्र को बचाने की कोई आखिरी उम्मीद बची है तो वह शायद ऐसे ही नेताओं में है जो सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। और बंगाल में आज वही हिम्मत ममता बनर्जी के रूप में खड़ी दिखायी दे रही है।

ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर पर भी आपत्ति

उन्होंने कमीशन पर पश्चिम बंगाल से ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अधिकारियों को बिना पहले से बताए दूसरे राज्यों में ट्रांसफर करने बदलने और डेपुटेशन देने के लिए भी हमला किया। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल की चुनी हुई मुख्यमंत्री हूं लेकिन इसके बावजूद मेरे अधिकारियों को बिना मुझे पहले से बताए ट्रांसफर कर दिया गया। अब राज्य में जरूरी और इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव कामों की जिम्मेदारी कौन लेगा? खाना कौन देगा? बाढ़ या तूफान जैसी कुदरती आफतों से कौन निपटेगा? अगर भाजपा ऐसे कामों से मुझे कुचलने की सोच रही है तो वह गलत है। उन्होंने एसआईआर को लेकर कहा कि यह शर्म की बात है कि पश्चिम बंगाल के नागरिकों को इतने सालों बाद अब अपनी नागरिकता का सबूत देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों को खास तौर पर लॉजिकल डिसक्रेपेंसी नोटिस भेजे गए थे और उन्हें यकीन है कि पश्चिम बंगाल में एनआरसी अगला एजेंडा होगा लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं एक भी व्यक्ति को डिटेंशन कैंप में नहीं जाने दूंगी

साधारण नहीं हैं आरोप

ममता का आरोप साधारण नहीं है। वह कहती हैं कि सुरक्षा बल जिन पर निष्पक्षता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अब बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। झंडा उठाए घूम रहे हैं यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक ऐसा आरोप है जो सीधे चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है। सोचिए अगर सुरक्षा बल ही पक्षपाती हो जाएं तो आम वोटर किस पर भरोसा करेगा? किसके सामने अपनी उंगली उठाएगा? लोकतंत्र का सबसे पवित्र दिन मतदान अगर डर दबाव और शक के साए में हो तो फिर लोकतंत्र का अर्थ ही क्या रह जाता है? ममता बनर्जी का यह हमला अचानक नहीं है। यह उस लंबे संघर्ष की अगली कड़ी है जिसमें वह खुद को दिल्ली की ताकत के खिलाफ खड़ा बताती रही हैं। चुनाव आयोग के फैसलों पर सवाल अधिकारियों के ट्रांसफर पर नाराजगी और अब सीएपीएफ पर आरोप। यह सब मिलकर एक बड़ी कहानी बुनते हैं। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। क्या यह सिर्फ राजनीतिक रणनीति है? या वाकई बंगाल में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देश की जनता से छुपाया जा रहा है?

सीएपीएफ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने उठाए सवाल

चुनाव आयोग से पंगे के बाद अब सुरक्षा बलों पर हमला

चुनाव आयोग के बाद अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय बल भी कमीशन की तरह ही पश्चिम बंगाल में भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है। सीएम ममता बनर्जी ने उत्तरी बंगाल में एक के बाद एक तीन रैलियों को संबोधित किया। एक रैली में उन्होंने राज्य में पहले से तैनात सीएपीएफ कंपनियों पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा के खिलाफ हर वोट चुनाव आयोग के खिलाफ बदला होगा जिसने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के जरिए लोगों को परेशानी दी है। उन्होंने आगे कहा कि वह सीएपीएफ का बहुत सम्मान करती हैं लेकिन अब उन्होंने देखा कि पश्चिम बंगाल में वे भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं और भाजपा के झंडे भी ले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं को इस बार मतदान के दिनों में सुबह से ही पोलिंग बूथ की सुरक्षा के लिए खास पहल करनी होगी। अगर आप पश्चिम बंगाल में पांच साल के लिए शांति चाहते हैं तो आपको एक दिन के लिए बूथ की सुरक्षा करनी होगी और बाहरी लोगों को चुनावी गड़बड़ी से रोकना होगा। आपके घर में जो कुछ भी है उसे लेकर सड़कों पर उतरें।

ममता बनर्जी का चुनाव आयोग से टकराव कोई नया नहीं है। लेकिन इस बार मामला और गंभीर हो गया है। उन्होंने आयोग पर आरोप लगाया कि वह बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर लोगों को परेशान कर रहा है। उनका कहना है कि सालों से यहां रह रहे लोगों से अचानक नागरिकता के सबूत मांगे जा रहे हैं। खासकर आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ममता ने इसे सीधे-सीधे एनआरसी की तैयारी बताया। उनका बयान जब तक मैं जिंदा हूं किसी को डिटेंशन कैंप नहीं जाने दूंगी एक मजबूत राजनीतिक संदेश है। लेकिन असली विस्फोट तब हुआ जब उन्होंने सीएपीएफ पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल बीजेपी के झंडे लेकर घूम रहे हैं और एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। यह आरोप सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि संस्थागत संकट की ओर इशारा करता है। अगर सुरक्षा बलों की निष्पक्षता पर सवाल उठता है तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया संदिग्ध हो जाती है। ममता का गुस्सा अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर भी है। उनका कहना है कि बिना राज्य सरकार को बताए अधिकारियों को हटाया जा रहा है जिससे प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है।

भाजपा सरकार सपा कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे लगा रही : अखिलेश

» सपा प्रमुख बोले- भाजपा लोकतंत्र विरोधी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर एकबार फिर तीखा प्रहार करते हुए उसे लोकतंत्र विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि वह सपा कार्यकर्ताओं पर फर्जी कार्रवाई करवा रही है। उन्होंने निवेश समझौतों में गड़बड़ी और तकनीक के गलत उपयोग की बात कही। आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। साथ ही त्योहारों की शुभकामनाएं दीं और संगठन में नए पदाधिकारियों की घोषणा की गई।

सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र विरोधी है। भाजपा सरकार समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे लगाती है। धमकी और अवैध कार्रवाई करती है। अखिलेश यादव प्रदेश सपा मुख्यालय पर विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव निकट आता जा रहा है, वैसे-वैसे भाजपा नेतृत्व बौखला रहा है।

उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का प्रयोग खेती, किसानी और अन्य सकारात्मक कार्यों के लिए करना चाहिए था, लेकिन भाजपा इसका प्रयोग विपक्ष के खिलाफ करती है।

सपा अध्यक्ष ने कहा कि एआई की एक कंपनी 2025 में बनी और 2026 में उससे 25 हजार करोड़ का एमओयू हो गया। इसके निदेशकों की कोई वैल्यू नहीं है। कहां से आकर इतना बड़ा एमओयू कर लिया। यूपी में इसके पहले भी इसी तरह के फर्जी एमओयू पकड़े गए थे। भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को हर क्षेत्र में बर्बाद कर दिया है।

पीडीए से डरे भाजपा नेता

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोगों को सोते-जागते केवल पीडीए ही दिखाई देता है। केवल पीडीए ही सुनाई देता है। लोकसभा में हार की हताशा और आने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता से बाहर होने के डर से ये पीडीए का नाम सुनते ही बेचैन हो जाते हैं।

रामनवमी की दी बधाई

सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दुर्गाष्टमी और रामनवमी के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को अनंत शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि अन्याय के विरुद्ध सत्य की जीत के इस पावन पर्व पर प्रभु श्रीराम के दैवीय और मानवीय चरित्र आज भी अनुकरणीय हैं।

रुक्मिणी देवी बनीं समाजवादी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष

सपा ने जालौन की रुक्मिणी देवी निषाद को समाजवादी महिला सभा उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नामित किया है। रुक्मिणी देवी निषाद को वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर लक्ष्य दिए गए हैं।

सोनिया गांधी की सेहत में सुधार

» तबीयत बिगड़ने पर सर गंगा अस्पताल में कराया गया था भर्ती

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी का सर गंगाराम अस्पताल में उपचार जारी है। अस्पताल के चेयरमैन डॉ. अजय स्वरूप ने बताया की सोनिया गांधी का इलाज सिस्टमिक इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स से किया जा रहा है।

यह इलाज डॉ. डी.एस. राणा, डॉ. एस. नंदी और डॉ. अरूप बसु की देखरेख में चल रहा है और इलाज का उन पर असर भी दिख रहा है। बता दें कि तबियत बिगड़ने पर मंगलवार रात करीब साढ़े दस बजे उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले अस्पताल के चेयरमैन डॉ. अजय स्वरूप ने बताया था कि पेट और यूरिनरी ट्रैक्ट में संभावित संक्रमण की जांच के लिए विभिन्न टेस्ट किए गए हैं। एहतियात के तौर पर उन्हें एंटीबायोटिक्स दी गई हैं और उनकी स्थिति पर करीबी नजर रखी जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की उपचार योजना तय की जाएगी।

पलानीस्वामी करिश्माई या प्रभावशाली नेता नहीं : पन्नीरसेल्वम

» डीएमके नेता ने विपक्ष पर किया तीखा प्रहार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चेन्नई। पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके नेता ओ पन्नीरसेल्वम ने विपक्ष पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि एडप्पाडी पलानीस्वामी करिश्माई या प्रभावशाली नेता नहीं हैं। 2017 से लेकर 2024 के संसदीय चुनावों तक, उन्हें 10 चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है। एक सच्चा मजबूत नेता विधानसभा या संसदीय चुनावों में हार के बाद भी अपनी पार्टी को अगले चुनाव में जीत दिलाने में सक्षम होना चाहिए। तभी उन्हें प्रभावशाली नेता माना जा सकता है।

इस मानदंड के अनुसार, एडप्पाडी पलानीस्वामी प्रभावशाली नेता नहीं हैं। लगातार दस चुनावी हार के बावजूद वे अपने पद पर बने हुए हैं। ओ पन्नीरसेल्वम ने कहा कि मैं प्रेस से इसलिए मिल रहा हूं ताकि देश की जनता को बता सकूं कि एडप्पाडी पलानीस्वामी द्वारा आज जारी किया गया चुनावी घोषणापत्र झूठा है। हमें

यह जांच करनी चाहिए कि एडप्पाडी पलानीस्वामी ने अतीत में जो वादे किए थे, क्या वे वास्तव में पूरे हुए हैं। द्रविड़ मुनेत्र कषगम् (द्रमुक) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर पलटवार करते हुए बुधवार को लोकसभा में कहा कि तमिलनाडु के और पार्टी के प्रमुख नेता हमेशा महिला अधिकारों के पक्षधर रहे हैं।

द्रमुक सांसद कलानिधि वीरास्वामी ने सदन में 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025' पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि तमिलनाडु हमेशा से महिला अधिकारों का पैरोकार रहा है। उनका कहना था कि चाहे पेरियार रहे हों, करुणानिधि रहे हों या फिर हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री स्टालिन, सभी महिला अधिकारों और सशक्तीकरण के पक्षधर रहे हैं। यह स्पष्ट होना चाहिए। इससे पहले, वित्त मंत्री सीतारमण ने सदन में वित्त विधेयक, 2026 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बयान का उल्लेख किया और कहा कि द्रमुक सरकार महिलाओं के खिलाफ है और इस बार महिलाओं का समर्थन उसे नहीं मिलेगा।

संसद में स्पीकर से जया बच्चन की तीखी नोकझोंक

» बोली रास सांसद- फांसी चढ़ा दीजिए, कमजोर लोगों को चढ़ा ही रहे हैं

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। राज्यसभा में ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण (संशोधन) बिल पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन और चेयर के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बोलने के लिए खड़ी हुईं जया बच्चन ने शुरुआत में सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं दीं, लेकिन बीच-बीच में व्यवधान के चलते उनका संबोधन बाधित हुआ।

डिप्टी चेयरमैन पैनल के सदस्य डॉ. दिनेश शर्मा ने उन्हें चेयर की ओर देखकर बोलने के लिए कहा, जिस पर जया बच्चन ने आपत्ति जताई और कहा कि अगर अन्य सदस्य बोल रहे हैं तो ध्यान उधर जाएगा। इसी दौरान उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा, आप लोगों के हाथ में सबका समय है, जितना मर्जी दीजिए, फांसी चढ़ा दीजिएज्ञ कमजोर लोगों को चढ़ा ही रहे हैं। इस टिप्पणी के बाद सदन का माहौल कुछ देर के लिए गरमा गया। बता दें कि इससे पहले भी कई मौकों पर जया बच्चन और स्पीकर के बीच तीखी नोकझोंक के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। जया बच्चनने ट्रेजरी बेंच की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्हें टोकने के बजाय व्यवधान पैदा करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि चेयर को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। अपने संबोधन में उन्होंनेट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भारतीय परंपरा में इस समुदाय का सम्मान रहा है और उन्हें शुभ अवसरों से जोड़ा जाता रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस समुदाय की समस्याओं, दर्द और वास्तविक स्थिति को समझने के बाद ही ऐसा कानून लाना चाहिए।

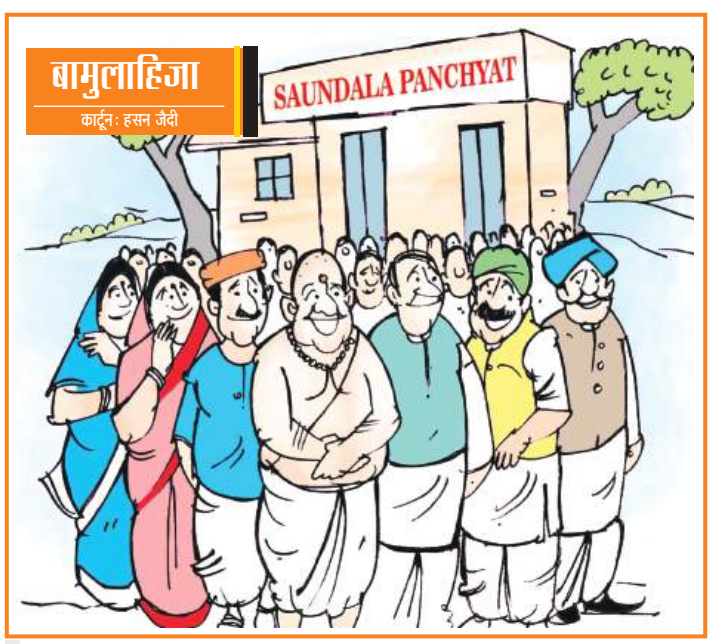

कांग्रेस नेता राज बब्बर बरी, दो वर्ष पहले निचली कोर्ट ने सुनाई थी सजा

» मतदान अधिकारी से मारपीट का था मामला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। 30 वर्ष पहले हुए चुनाव में वोटिंग के दौरान मतदान अधिकारी एवं अन्य लोगों से मारपीट करने समेत अन्य मामले के आरोपी राज बब्बर को बरी कर दिया गया है।

समाजवादी पार्टी के तत्कालीन प्रत्याशी राज बब्बर को दो साल की सजा दिए जाने के निचली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपील को एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंस नारायण ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने राजबब्बर को आरोपों से बरी करते हुए निचली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। इसके पहले कोर्ट में सुनवाई के

समय राज बब्बर हाजिर हुए। कोर्ट ने कांग्रेस नेता राज बब्बर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनको निचली अदालत की ओर से सुनाई गई दो साल की कैद और 6500 रुपये के जुर्माने की सजा को समाप्त करते हुए बरी कर दिया।बताते चलें सात जुलाई 2022 को एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्ब्रिश श्रीवास्तव ने राज बब्बर को भारतीय दंड संहिता की धारा 143 में छह महीने की कैद और 1000 रुपये का जुर्माना, धारा 332 में दो साल की कैद और 4000 रुपये जुर्माना, धारा 353 में एक वर्ष की कैद और 1000 रुपये का जुर्माना और धारा 323 में छह माह की कैद और 500 रुपये का जुर्माना लगाया था। पत्रावली के अनुसार मामले की रिपोर्ट दो मई 1996 को मतदान अधिकारी कृष्ण सिंह राणा ने थाना वजीरगंज में राज बब्बर एवं अरविंद यादव के अलावा अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई थी।

विधेयकों को पास करवाने में नहीं चल रही मनमानी

सीएपीएफ व कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक बिल पर रार

कई विधेयक संसद में नहीं हुए पास, सरकार पीछे हटी

- कई को भेजना गया संसदीय समिति की चौखट पर
- विपक्ष ने जल्दबाजी में कानून पारित करने के खिलाफ दी चेतावनी
- कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सीपीआई (एम) ने सरकार का किया विरोध

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार की मनमानी नहीं चल पा रही है। इसबार कई विधेयकों को भाजपा आसानी से संसद से पास नहीं करवा पा रही है। पिछले दो सालों में कई विधेयक या तो उसने वापस ले लिए या उसे जेपीसी को भेज दिया। ऐसा देखने को मिल रहा है कि विपक्ष के दबाव में सरकार बैकफुट पर चली जा रही है हालांकि उसका बहुमत है। ताजा इस सत्र का जिसमें विपक्ष के विरोध के बाद सीएपीएफ व कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक बिल राज्यसभा में नहीं पेश हो सका।

वहीं संसद में पेश कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक पर सरकार और विपक्ष के बीच घारे मतभेद दिखे, जिसके बाद सरकार ने इसे व्यापक विचार-विमर्श हेतु जेपीसी को भेजने का निर्णय लिया। राज्यसभा में सीएपीएफ बिल पेश करने की सरकार की कोशिश विपक्ष के कड़े विरोध के कारण टल गई। तृणमूल कांग्रेस समेत कई दलों ने आरोप लगाया कि बिल की प्रति सांसदों को तय 48 घंटे पहले उपलब्ध नहीं कराई गई, जो संसदीय नियमों का उल्लंघन है। राज्यसभा में सोमवार को केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) विधेयक को पेश करने की प्रक्रिया प्रभावित हुई। दरअसल विपक्षी दलों ने संसदीय नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इस पर कड़ा विरोध जताया। तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में कई विपक्षी दलों ने दावा किया कि बिल की प्रति सदस्यों को निर्धारित 48 घंटे पहले उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके चलते इसकी पेशी को रोका गया।

कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक पर कांग्रेस का घोर विरोध, बैकफुट पर सरकार

लोकसभा में आज भी जोरदार हंगामा बना रहा। संसद में पेश कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक पर सरकार और विपक्ष के बीच घारे मतभेद दिखे, जिसके बाद सरकार ने इसे व्यापक विचार-विमर्श हेतु जेपीसी को भेजने का निर्णय लिया। कांग्रेस ने प्रमुख नीतिगत मामलों को अधीनस्थ कानूनों पर छोड़ने का विरोध किया है, जबकि सरकार का लक्ष्य व्यवसायों के लिए मुकदमेबाजी का जोखिम कम करना है। कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजने का प्रस्ताव रखा। सदन ने इस पर सहमति जताते हुए विधेयक को जेपीसी को भेज दिया।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने उठाए सवाल

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 को पेश किए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कंपनियों का वर्गीकरण, छूट, अनुपालन आवश्यकताओं का निर्धारण,

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की सीमा, लेखापरीक्षा दायित्व और दंड ढांचे जैसे प्रमुख नीतिगत मामलों को पर्याप्त विधायी मार्गदर्शन के बिना बार-बार निर्धारित प्रावधानों के उपयोग के माध्यम से अधीनस्थ कानूनों पर छोड़ दिया गया है।

क्या है सीएपीएफ बिल?

प्रस्तावित सीएपीफ बिल का उद्देश्य देश के 5 प्रमुख केंद्रीय सुरक्षा बलोसीआरपीफ, बीएसएफ, आईटीबीपी,एसएसबी, सीआईएसएफ के लिए एकीकृत प्रशासनिक ढांचा तैयार करना है। फिलहाल ये सभी बल अलग-अलग कानूनों के तहत संचालित होते हैं। बिल के तहत भर्ती, प्रमोशन, डेपुटेशन और सेवा शर्तों को एक समान बनाने का प्रस्ताव है। इसमें आईपीएस अधिकारियों की वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति को औपचारिक रूप देने की बात भी शामिल है। बिल के अनुसार, इंस्पेक्टर जनरल (आईजी) स्तर के 50 प्रतिशत पद आईपीएस अधिकारियों के जरिए भरे जाएंगे, जबकि एडिशनल डायरेक्टर जनरल (एडीजी) स्तर पर यह संख्या कम से कम 67 प्रतिशत होगी। शीर्ष पदों स्पेशल डायरेक्टर जनरल (एसडीजी) और डायरेक्टर जनरल (डीजी) पर पूरी तरह आईपीएमस अधिकारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव है। इसी प्रावधान को लेकर विवाद गहराया हुआ है, क्योंकि सीएपीफ के भीतर से ही अधिकारियों के अवसर सीमित होने की आशंका जताई जा रही है।

सरकार ने विचार-विमर्श के लिए जेपीसी को भेजा

विधायक द्वारा विधेयक पेश किए जाने पर उठाई गई आपत्तियों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष ने जेपीसी द्वारा समीक्षा की मांग नहीं की थी। उन्होंने आगे कहा कि विधेयक को समिति को भेजने का निर्णय सरकार का था ताकि इस कानून पर व्यापक चर्चा हो सके। प्रमुख अपेक्षित प्रावधानों में से एक है छोटे कॉर्पोरेट अपराधों को और अधिक अपराध की श्रेणी से बाहर करना, जो प्रक्रियात्मक चूक के लिए आपराधिक दंडों को मौद्रिक जुर्माने से बदलने के सरकार के पूर्व दृष्टिकोण को जारी रखता है। इसका उद्देश्य मुकदमेबाजी के जोखिम को कम करना और व्यवसायों के लिए परिचालन तनाव को कम करना है।

शाह ने की विपक्षी नेताओं के साथ बैठक कर सहमति बनाने की कोशिश

स्थिति को देखते हुए सरकार ने फिलहाल सीएपीएफ बिल को पेश करने का फैसला टाल दिया। एक वरिष्ठ मंत्री ने स्वीकार किया कि कुछ मतभेद सामने आए हैं, जिन्हें दूर करना आवश्यक है। इस बीच गृह मंत्री अमित

शाह ने विपक्षी नेताओं के साथ बैठक कर सहमति बनाने की कोशिश की। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी इस बैठक में शामिल रहे। वहीं, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अन्य दलों के नेताओं के साथ अलग से रणनीति बैठक की।

इसी महीने की शुरुआत में मंजूरी

विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसी महीने की शुरुआत में मंजूरी दे दी है और यह कंपनी विधि समिति (2022) की सिफारिशों के साथ-साथ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से प्राप्त सुझावों पर आधारित है। इसमें दो प्रमुख कानूनों - कंपनी अधिनियम, 2013 और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 - में संशोधन का प्रस्ताव है, जो मिलकर पूरे भारत में कॉर्पोरेट संस्थाओं और एलएलपी को नियंत्रित करते हैं। मूल रूप से, इस विधेयक का उद्देश्य अनुपालन के बोझ को कम करना, छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना और समय के साथ उभरे नियामकीय अंतरालों को दूर करना है।

अन्य संबंधित विधायी मामले जो जेपीसी में गए

एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) सरकार द्वारा लाए गए और व्यापक चर्चा/सहमति के लिए संसदीय समिति (जेपी या स्टैंडिंग कमेटी) के पास भेजे गए प्रमुख विधेयकों में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 सबसे प्रमुख है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 वक्फ बोर्ड के कामकाज और संपत्ति के प्रबंधन को विनियमित करने के लिए लाए गए इस विधेयक को व्यापक विरोध और चिंताओं के बाद संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को जांच के लिए भेजा गया था। 2024 के आम चुनावों के बाद, वक्फ बोर्ड बिल के अलावा, अन्य सुधारवादी विधेयकों को भी संसदीय समितियों के माध्यम से बारीकी से जांचने की रणनीति रही है।

संसदीय प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित हो : डेरेक ओ ब्रायन

तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने सदन में यह मुद्दा उठाते हुए सरकार से संसदीय प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने की मांग की। विरोध के बीच पार्टी के सांसदों ने वॉकआउट भी किया। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सीपीआई (एम) ने भी इस मुद्दे पर सरकार का विरोध किया और जल्दबाजी में कानून पारित करने के खिलाफ चेतावनी दी।

सरकार की जवाबदेही तय करती हैं संसदीय समितियां

संसदीय समितियां सांसदों का एक पैनल हैं, जिन्हें सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है। ये समितियां, संसद के पास समय की कमी होने के कारण, कानूनों की गहन जांच, सरकारी कामकाज के निरीक्षण और बजटीय मामलों के अध्ययन में सहायता करती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य संसद के कार्यभार को कम करना, कानून की बारीकी से जांच करना और सरकार की जवाबदेही तय करना है। ये समितियां, लोकसभा अध्यक्ष या सभापति के निर्देशन में काम करती हैं। समितियां स्थायी (जैसे- लोक लेखा समिति) या तदर्थ (विशिष्ट उददेश्यों के लिए) प्रकार की हो सकती हैं। भारतीय संसद में मुख्य रूप से दो प्रकार की समितियां होती हैं—स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। सबसे महत्वपूर्ण स्थायी विभागीय समितियों की संख्या 24 है, जिनमें से 16 लोकसभा और 8 राज्यसभा के अंतर्गत कार्य करती हैं। ये समितियां मंत्रालयों की जांच और अनुदान मांगों पर काम करती हैं। स्थायी समितियां ये निरंतर कार्य करती हैं, जिनमें वित्तीय समितियां (लोक लेखा, प्राक्कलन, सार्वजनिक उपक्रम) और 24 विभागीय समितियां शामिल हैं। तदर्थ समितियां ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए गठित की जाती हैं और कार्य पूरा होने पर समाप्त हो जाती हैं। सदस्य संख्या प्रत्येक विभागीय समिति में 31 सदस्य होते हैं (लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10)।

Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma

@Editor_Sanjay

जिद... सच की

लचीली और बहुआयामी हो शिक्षा प्रणाली

आज विश्व में जैसी शिक्षा प्रणाली बदल रही है ऐसे में भारत में भी बदलाव की आवश्यकता है। भविष्य उन्मुख तकनीकी पाठ्यक्र मों की जरूरत है। चूकि भारत के हजारों बच्चे नौकरी करने विदेशों में जाते हैं ऐसे में उन्हें वहा परेशानी न हो इसलिए उन्हें नई विधा में पारंगत होना होगा तभी वह वैश्विक मुकाम हासिल कर पाएंगे। वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा, मशीन लर्निंग, डिजिटल तकनीक और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसे पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को वैज्ञानिक सोच के साथ रोजगार के लिए तैयार करें। शिक्षा केवल सैद्धांतिक न होकर नवाचार और व्यावहारिकता से जुड़ी हो, ताकि छात्र बदलती दुनिया के अनुरूप खुद को ढाल सकें। पाठ्यक्रम ऐसे हों जो डिग्री के साथ-साथ विद्यार्थियों में तकनीकी दक्षता और व्यावहारिक समझ विकसित करें। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि रोजगार योग्य बनाना भी होना चाहिए। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा, उद्यमशीलता, डिजिटल मार्केटिंग, अंतरराष्ट्रीय कानून और वित्तीय साक्षरता जैसे विषय शामिल हों।

स्थानीय समझ और वैश्विक कौशल का संतुलन आज की आवश्यकता है। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए उनकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। उन्हें प्रश्न पूछने, तर्क करने और स्वयं समाधान खोजने का अवसर मिलना चाहिए। प्रयोग आधारित शिक्षा, विज्ञान किट, पुस्तकों और प्रकृति अवलोकन से सीखना अधिक प्रभावी बनता है। असफलताओं को सीख का हिस्सा मानते हुए संवाद और डिजिटल संसाधनों का रचनात्मक उपयोग बच्चों की सोच को गहराई देता है। स्कूल शिक्षा में ऐसा वातावरण बनाया जाना चाहिए जो विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करे। इससे उनकी सृजनशीलता बढ़ेगी और पढ़ाई के प्रति रुचि भी मजबूत होगी। वैज्ञानिक सोच न केवल ज्ञान बढ़ाती है, बल्कि समस्याओं को समझने और समाधान खोजने की क्षमता भी विकसित करती है, जो आज के समय में अत्यंत आवश्यक है। उच्च गुणवत्ता वाली समावेशी शिक्षा के लिए पाठ्यक्रमों को पारंपरिक ढांचे से बाहर निकालना होगा। इन्हें आधुनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक कौशलों पर केंद्रित किया जाना चाहिए। साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भविष्य की नौकरियों के लिए व्यावसायिक, व्यवहारिक और कौशल आधारित शिक्षा का संतुलित मॉडल अपनाना आवश्यक है।

शिक्षा प्रणाली को ऐसा बनाया जाना चाहिए जो विद्यार्थियों को रोजगार योग्य, नवाचारी और सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनाए। आज केवल पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है। पाठ्यक्रमों को लचीला और बहुआयामी बनाकर तकनीकी और जीवनोपयोगी शिक्षा पर जोर देना होगा, ताकि विद्यार्थी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सकें।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

संतुलन के लिए जरूरी रणनीतिक दिशा तय करना

गुरबचन जगत

जून, 1914 में ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या उन मुख्य घटनाओं में से एक मानी जाती है जिनके परिणाम में प्रथम विश्वयुद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में अंतर्निहित बड़ा कारण था कि 'केंद्रीय शक्तियां' (जर्मनी, ऑस्ट्रिया-हंगरी और ओटोमन साम्राज्य) दुनियाभर में साम्राज्यवादी विस्तार और औपनिवेशीकरण करने की दौड़ में देर से शामिल हुईं, जिसमें ब्रिटेन व फ्रांस वर्चस्व कायम कर चुके थे। कैसर विल्हेम द्वितीय के नेतृत्व में जर्मनी ने साम्राज्य स्थापना की महत्वाकांक्षा पाली थी,और इसी के चलते तनाव-संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। बाकी सब इतिहास है। चार साल (1914-18) चले युद्ध में सैन्य व नागरिक हताहतों की संख्या 1.5 से 2.2 करोड़ होने का अनुमान है।

वर्साय संधि पर हस्ताक्षर के साथ युद्ध औपचारिक रूप से खत्म हो पाया। लेकिन दुखद, इंसान की स्मृति इतनी कमजोर कि शायद ही कोई साल गुजरता हो जब विश्व में कहीं न कहीं हिंसा न भड़कती हो। व्यक्तियों की तरह, गरीब देश भी आपस में नहीं लड़ते-सिवाय कुछ मामलों के जहां विकास अभी कबीलाई चरण में है। अमीर, विकसित और सैन्य रूप से शक्तिशाली देश ही परस्पर लड़ते हैं, या फिर गरीब लेकिन प्राकृतिक संसाधन समृद्ध राष्ट्रों को उपनिवेश बनाने की कोशिश करते हैं। धर्म व नस्ल की इसमें अहम भूमिका हैं-अमूमन छद्म रूप में। किसी इंसान या देश को आखिर कितनी जमीन चाहिए? क्या यह कभी काफी रही? या फिर यह कि आप जितने अधिक शक्तिशाली होते हैं, लालसी उतनी ही बढ़ती जाती है? प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जर्मनी, जापान और इटली ('धुरी की शक्तियां') अपने विशाल संसाधन के बूते धीरे-धीरे शक्तिशाली राष्ट्रों के रूप में उभरे; लेकिन इसके बावजूद उन्होंने यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, प्रशांत द्वीपों और एशिया को जीतने का प्रयास किया। शक्तिशाली देशों को सदा प्रगति की जरूरत रहती है; यथास्थिति कभी पर्याप्त नहीं रही। उन्हें और भूमि व संसाधन चाहिए होते हैं, लूटने के लिए और धन व गुलाम बनाने को और अधिक स्त्री-पुरुष चाहिए होते हैं।

इसी कारण द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ गया, जिसमें करोड़ों जानें गई और शहर और देश तबाह हुए। द्वितीयविश्व युद्ध में हुआ नुकसान प्रथम विश्वयुद्ध के मुकाबले कहीं अधिक था। आज दौड़ दुर्लभ भू-खनिजों, आपूर्ति शृंखलाओं और इनके खनन, प्रसंस्करण से चुंबक बनाने की पूरी मूल्य शृंखला को सुरक्षित

करने की लगी है। अमेरिका और चीन जैसी विशाल अर्थव्यवस्थाओं को इनकी जरूरत है, ठीक वैसे ही जैसे उन्हें अपने बड़े-बड़े डेटा सेंटर चलाने के लिए बेतहाशा ऊर्जा चाहिये। चूंकि हर चीज को जीडीपी वृद्धि के रूप में आंका जाता है, इसलिए कंपनियों के लिए ग्रोथ जरूरी है और मुकाबला बहुत कड़ा, गलाकाट है। निजी उद्योग से शुरू हुआ यह मामला धीरे-धीरे सियासी अखाड़े में फैल जाता है और जल्द ही सेनाएं भी आकर शामिल हो जाती हैं। 'कटिंग ऑफ द चाईनीज मेलन' (चीन को कब्जाने की तत्कालीन औपनिवेशिक ताकतों में होड़) से लेकर 'स्क्रैबल फॉर अफ्रीका'(अफ्रीकी देशों को गुलाम बनाने की दौड़) तक, इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जब बड़ी ताकतों ने अपनी जरूरतें पूरी करने को कमजोर देशों की अर्थव्यवस्थाओं और संसाधनों को आपस में बांट लिया। रूस, जिसके पास असीम भूमि है, यूक्रेन को पाना चाहता है-जिसे उसने सोवियत संघ के विघटन के साथ खो दिया था। यूक्रेन अपने मानव संसाधन, जमीन, परमाणु स्रोत और समुद्र तक पहुंच मार्ग के मामले में बहुत समृद्ध है, और रूस इसे पाना चाहता है। हमला करने का मौका तब मिला जब आशंका फलीभूत हुई कि नाटो यूक्रेन के जरिए रूस बॉर्डर तक प्रभाव बढ़ाना चाहता है। नाटो को भी यूक्रेन में वैसा ही मौका दिखा और वह भी उसके संसाधनों को बांटना चाहता है, जिसमें अमेरिकी स्पष्ट रूप से युद्ध का हर्जाना मांग रहा है। वेनेजुएला, अपने विशाल तेल भंडारों के साथ, अमेरिका के लिए आसान शिकार रहा। क्यूबा और ग्रीनलैंड अब सूची में अगले क्रम में हैं। वहीं इस्राइल मध्य-पूर्व को मर्जी मुताबिक ढालना चाहता है, वहीं ईरान की अपनी योजना है।

जैसे रूस ने यूक्रेन पर पूर्व-हमला कर दिया था, वैसे ही अमेरिकियों-इस्राइलियों ने ईरान को न्यूक्लियर बम और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल निर्माण से रोकने को उस पर वार किया। तेल समृद्ध खाड़ी देश सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं और इसलिए नुकसान झेल रहे हैं, वैसे ही जैसे ईरान की अप्रत्याशित युद्ध नीति व प्रतिक्रिया के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था हानि झेल रही है। बीते जमाने में, युद्ध थमने के बाद संधियों और संगठनों के जरिये आशा की किरण जगी बतौर लीग ऑफ नेशन्स के उत्तराधिकारी राष्ट्र संघ की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा यकीनी बनाए रखने के उद्देश्य से हुई।

भगत सिंह के मार्क्सवादी विचारों की तार्किकता

भगवान जोश

'भगत सिंह न केवल भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारी समाजवादियों में से एक थे, बल्कि वे शुरुआती मार्क्सवादी विचारकों-सिद्धांतकारों में से भी एक थे। उनका बाद वाला पहलू अपेक्षाकृत कम ज्ञात है, फलत: प्रतिक्रियावादी, रूढ़िवादी और सांप्रदायिक लोग अपनी राजनीतिक विचारधारा हेतु भगत सिंह और साथियों-जिनमें चंद्रशेखर आजाद भी शामिल हैं- के नाम-यश का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं।' उपरोक्त शब्द मेरे मार्गदर्शक, प्रो. बिपन चंद्र ने भगत सिंह के बीस-पृष्ठों वाले लेख 'मैं नास्तिक क्यों हूं' की प्रस्तावना में लिखे थे; लेख पंजाबी कवि अमरजीत चंदन ने 1979 में खोजा था। पिछले 40 वर्षों में, भगत सिंह का यह ऐतिहासिक मूल्यांकन निर्विवाद तथ्य की ताकत पा चुका है। पाठकों के मानस में बैठाने को उनकी 'जेल नोटबुक' के कई संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं कि यह किताब प्रतिष्ठित विचारकों और दार्शनिकों के विचारों की भगत सिंह द्वारा की गई पड़ताल एक नई खिड़की खोलती है।

गदर आंदोलन के इतिहासकार हरीश पुरी लिखते हैं—'हालांकि जहां कहीं से उन्होंने ये नोट्स या उद्धरण उठाए, उन स्रोतों या किताबों के बारे में दी गई अधूरी जानकारियों ने एक उलझन भरा प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है। यानी, ये उद्धरण किन लेखकों विशेष से, किन किताबों के किस संस्करण से लिए गए थे? फलत: भगत सिंह जेल में जिन महान विचारकों की किताबों-रचनाओं का अध्ययन कर पाए थे, उसको लेकर उनके प्रशंसक विद्वानों ने कई मनगढ़ंत दावे-बेबुनियाद अटकलें लगा लीं।' 1925 से 1928 के बीच, भगत सिंह ने बहुत ज्यादा पढ़ा; उन्होंने रूसी क्रांति व सोवियत संघ पर लिखी किताबें पढ़ीं। 1920 के दशक में, क्रांतिकारी आंदोलनों पर सबसे अधिक जानकारी रखने वालों में भगत सिंह का नाम भी शामिल था। वर्ष 1928 के अंत में उन्होंने व साथियों ने समाजवाद को अपनी गतिविधियों का अंतिम लक्ष्य मान अपने संगठन का नाम 'हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन' से बदलकर 'हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' कर दिया था।

सवाल है कि क्या भगत सिंह को मार्क्सवाद से भारतीय राष्ट्रवाद की समकालिक राजनीति, मजदूर वर्ग के आंदोलनों और ऐतिहासिक-सामाजिक यथार्थ को समझने में मदद मिली? मार्क्सवाद पर ऐसी महारत, जो सिर्फ किताबों में लिखी बातों को समझने का एक अभ्यास भर हो, वह 'ब्राह्मणवादी मार्क्सवाद' बनकर ही रह जाएगा; जब तक कि वह पार्टी के बुद्धिजीवियों को 'व्यावहारिक सिद्धांत' का एक ढांचा पेश कर, समय की सामाजिक सच्चाई से निष्पक्ष होकर जुड़ने में मदद न करे। तो फिर, किसे मार्क्सवादी विचारक कहा जा सकता है? यह सवाल इटली के बुद्धिजीवी एंटोनियो ग्राम्शी की याद दिलाता है, जो ठीक भगत सिंह की तरह ही, और ठीक उसी समय, फासीवादी मुसोलिनी की जेल में, 1937 में अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले तक कैद में रहे।

इन कठिन परिस्थितियों में भी, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन की ठोस समस्याओं, उसकी असफलताओं और सफलताओं को समझने-सुलझाने के लिए अपना पढ़ने-लिखने का काम जारी रखा। इन दिनों, पश्चिम एशियाई संकट की बहसों में, ट्रंप और नेतन्याहू के रणनीतिक लक्ष्यों को समझाने के लिए 'आधीनता की अवधारणा' का खूब जिक्र किया जाता है। तथ्य यह है कि वहां सत्ता परिवर्तन के लिए अमेरिका और इस्राइल को सबसे पहले ईरानी समाज पर हावी होकर उसे पूरी तरह से झुका डालना होगा। जब कोई राष्ट्र या समाज, किसी दूसरे सामाजिक समूह द्वारा शासित होने के लिए जबरदस्ती से मजबूर किया जाता है, तभी 'आधीनता' स्थापित हो पाती है। पराजित लोगों के लिए यह बहुत ही कठिन क्षण होता है। उदाहरणार्थ, 1857 के नाराज भारतीय विद्रोहियों को, ब्रिटिश सेना और सिख सैनिकों द्वारा हराए जाने के बाद, ब्रिटिश राज की आधीनता स्वीकार करने के लिए तब राजी हो पाए, जब उन्होंने देखा कि उनके कुलीन वर्ग को राज का हिस्सा बना लिया गया है। सर सैयद अहमद खान, जिन्हें 1888 में ब्रिटिश सरकार द्वारा 'नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया' के सम्मान से नवाजा गया था- उन्हें अपने साथ जोड़कर नए शासकों की आधीनता स्वीकार करने के लिए राजी किया गया। उन्होंने भारतीय मुसलमानों के बीच विमर्श रखा कि समुदाय की तरक्की के लिए सहयोग, अथवा ब्रिटिश आधीनता को स्वीकार्य करना जरूरत है।

भाव यह कि सत्ता परिवर्तन के बिना आधीनता कायम नहीं की जा सकती। भगत सिंह का मानना था कि गांधी का अहिंसा का मार्ग, भारत को अर्ध-अधीनस्थ राष्ट्र बनाने में सहयोग करने जैसा है। इसीलिए साइमन विरोधी प्रदर्शनों के दौरान, भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय पर हुए लाठीचार्ज का दोष ब्रिटिश अधिकारी जेम्स स्कॉट पर मढ़ा, लेकिन वे इस बात से अनजान रहे कि असल में यह पंजाब पुलिस के सिपाही थे, जिन्होंने उन्हें पीटा था। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का मानना था कि ब्रिटिश वर्चस्व की ताकत इतनी भर है कि अगर गांधी आड़े न आएं, तो वे ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने में कामयाब हो जाएंगे। परंतु वे यह नहीं देख पाए कि वही ब्रिटिश राज उन्हें मीडिया के जरिए अपने विचारों का प्रचार करने की अनुमति कैसे और क्यों कर दे रहा है, उन्हें अदालत तक में क्रांतिकारी गीत गाने की छूट क्यों मिली, अथवा जेल अधिकारी उन्हें किताबें पढ़ने की इजाजत क्यों देते हैं।

कच्चे पपीते से घर पर ऐसे बनाएं अचार

भारतीय रसोई में अचार का खास महत्व है, यही वजह है कि लोगों के घरों में तरह-तरह के अचार पाए जाते हैं। अगर आप आम का अचार खाकर बोर हो गए हैं तो एक बार कच्चे पपीते का अचार ट्राई कर सकते हैं। कच्चा पपीता पाचन को बेहतर बनाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और लंबे समय तक खराब नहीं होता। इसकी सबसे खात बात ये है कि अचार जल्दी तैयार हो जाता है और इसे किसी भी मौसम में बनाया जा सकता है। जिन लोगों को तीखा-खट्टा स्वाद पसंद है, उनके लिए यह एक परफेक्ट विकल्प है। घर पर बना अचार न सिर्फ शुद्ध होता है बल्कि बाजार के अचार से ज्यादा स्वादिष्ट और सुरक्षित भी होता है।

सामान

कच्चा पपीता- 1 किलो, नमक - स्वादानुसार, हल्दी -1 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर- 2 छोटी चम्मच, राई (सरसों) पाउडर- 3 बड़ी चम्मच, सौंफ पाउडर- 2 बड़ी चम्मच, हींग - 1 चुटकी, सरसों का तेल - 200 एमल, सिरका / नींबू रस - 2 बड़ी चम्मच।

विधि

इसे बनाने के लिए सबसे पहले 1 किलो कच्चा पपीता धोकर उसके बीच के बीज निकाल दें और पपीते छोटा-छोटा काट लें। चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। कटे हुए पपीते को साफ कपड़े पर फैलाकर 20-30 मिनट धूप में रखें ताकि उसमें मौजूद अतिरिक्त नमी पूरी तरह सूख जाए। एक बड़े सूखे बर्तन में कटे हुए पपीता लेकर सभी मसाले डालें और सूखी चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करें। कच्चे पपीते का अचार कैसे बनाएं? अब 200-250 मिली सरसों का तेल कढ़ाही में डालकर तेज आंच पर तब तक गर्म करें जब तक हल्का धुआं न निकलने लगे। तेल को गैस से उतारकर पूरी तरह ठंडा होने दें और फिर पपीते के मिश्रण में डालकर मिलाएं। अगर आप थोड़ा खट्टा स्वाद चाहते हैं तो 2 बड़ी चम्मच नींबू का रस या सिरका मिला सकते हैं। अब अचार को साफ और सूखे कांच के जार में भर दें और जार को 4-5 दिन धूप में रखें। रोज़ एक बार साफ, सूखे चम्मच से अचार को हिला दें ताकि मसाले बराबर बैठें। 5-7 दिनों में कच्चे पपीते का अचार पूरी तरह तैयार हो जाता है। ये अचार दाल-चावल, पराठे, पूड़ी और सब्ज़ी के साथ बेहद स्वादिष्ट लगता है।

वजन घटाने के लिए रोज खाएं अमरूद चाट

जब भूख हल्की हो लेकिन कुछ चटपटा खाने का मन हो, तब अमरूद चाट से बेहतर विकल्प शायद ही कोई हो। अमरूद भारतीय रसोई का वो फल है जो सस्ता भी है, आसानी से मिलता है और पोषण से भरपूर भी है। अमरूद में विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। अमरूद पाचन सुधारता है, इम्युनिटी बढ़ाता है और वजन कंट्रोल में मदद करता है। हेल्दी स्नेक्स का जमाना है, जिसके नाम पर लोग प्रोटीन बार और पैकेट वाले स्नेक्स का सेवन करते हैं। जबकि असली सेहत तो हमारी परंपरागत थाली में छिपी है। अमरूद चाट उसी परंपरा की याद दिलाती है, बिना तेल, बिना चीनी और बिना मिलावट बनाई जाती है।

सामग्री

2 पके लेकिन सख्त अमरूद, आधा छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, एक चुटकी लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच नींबू रस, थोड़ा सा हरा धनिया वैकल्पिक है।

विधि

अमरूद को अच्छे से धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक बाउल में अमरूद डालें। ऊपर से काला नमक, चाट मसाला, भुना जीरा और लाल मिर्च डालें। नींबू रस मिलाकर हल्के हाथ से मिक्स करें। ऊपर से धनिया डालकर तुरंत परोसें। स्वाद बढ़ाने के देसी ट्विस्ट बच्चों के लिए थोड़ा सा शहद डाल सकते हैं, वेट लॉस डाइट के लिए सिर्फ काला नमक और नींबू रखें, स्ट्रीट स्टाइल फ्लेवर चाहिए तो ऊपर से थोड़ा सा कच्चा आम पाउडर मिलाएं। इस चाट को खाने से पाचन तंत्र को मजबूत करता है, कब्ज की समस्या में राहत, इम्युनिटी बूस्ट करता है। वजन घटाने में सहायक है, ये डायबिटीज फ्रेंडली फल है।

हंसना मना है

हर आदमी का सपना-7 अंकों में सॅलरी, 6 अंको में बचत, 5 बेडरूम वाला घर, 4 पहियों की गाड़ी, 3 हसे की छुट्टियां, 2 प्यारे बच्चे, 1 गूंगी बीवी।

मुर्गी- एक अंडा देना, शॉपकीपर- अंडा तो तुम देती हो, मुर्गी- हा पर मेरे पति ने कहा है, की 4 रु के लिए क्यों अपना फिगर खराब कर रही हो!

जब घर में बच्चा पैदा होता है, मां- इसकी नाक तो मुझ पर गयी है, बाप-आंखे मुझ पर गयी है, चाचा- बाल मुझ पर गए है, मां- इसकी स्माइल मुझ पर गयी है, और वही बच्चा जवान होकर जब लड़की छेड़ता है, तो सब बोलते है, पता नहीं हरामखोर किस पर गया है।

टीचर- बताओ सबसे नशीला पदार्थ कौन सा होता है? पप्पु - किताब है सर, साला खोलते ही नींद आ जाती है।

मनोहर: क्या एक वाईफ अपने हसबैंड को लखपती बना सकती है? गजोधर: हां, पर हसबैंड करोड़पती होना चाहिए।

कहानी — बुद्धिमान राजा

सालों पहले एक नगर में एक बुद्धिमान राजा राज्य करता था। उनकी बुद्धि और होशियारी की चर्चा दूर-दूर तक थी। राजा कभी भी बिना सोचे-समझे कुछ नहीं कहता और न ही किसी आरोपी की बात सुने बिना उसे सजा सुनाता था। उसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे सुनकर आसपास के राजा, रानियां और राजकुमारी आदि उनसे जलते थे। इसी जलन के चलते सभी उस राजा की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए नए-नए तरीके अपनाते थे। एक दिन राजा की परीक्षा लेने के लिए एक राजकुमारी आई। उसके हाथों में दो फूलों की माला थी। दोनों माला में से एक असली फूल से बनी थी और दूसरी नकली से। उन दोनों मालाओं को देखकर उनका ये भेद बिल्कुल पता नहीं चल पाता था। राजकुमारी ने पूछा कि हे राजन! अगर आप बुद्धिमान हैं, तो बताइए कि इनमें से कौन-सी माला असली है। राजदरबार में बैठे सभी दरबारी माला को देखकर हैरान थे, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि असली फूलों की माला कौन-सी है। सभी इस सोच में थे कि राजा कैसे बता पाएंगे कि असली फूलों की माला कौन-सी है। राजा भी माला को देखकर परेशान होने लगे। उसी वक्त उनके दिमाग में कुछ तरकीब आई। उन्होंने तुरंत अपने एक सेवक से कहा कि बगीचे की खिड़कियों को खोल दो।' सेवक ने बगीचे की खिड़की को जैसे ही खोला, तो राजा ने देखा कि फूल में बैठी मधुमक्खियां खिड़कियों से राज दरबार में आ रही हैं। वो कुछ देर मधुमक्खियों को ही देखते रहे। जैसे ही एकात मधुमक्खी एक फूल की माला में बैठी, वैसे ही राजा ने कहा कि अब मैं बता सकता हूं कि असली माला कौन-सी है। राजा ने तुरंत उस माला की तरफ इशारा किया, जिसपर मधुमक्खी बैठ रखी थी। राजा की होशियारी देखकर दरबार में मौजूद सभी उनकी तारीफ करने लगे। सभी कहने लगे कि हर राज्य को आपके जैसे ही बुद्धमान राजा की जरूरत है। राजकुमारी भी राजा के बुद्धिमत्ता देखकर खुश हो गई। उसने भी बुद्धिमान राजा की तारीफ में कुछ शब्द कहे और वहां से अपने राज्य की ओर निकल पड़ी।

7 अंतर खोजें

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष — पुराना रोग उभर सकता है। योजना फलीभूत होगी। कार्यस्थल पर परिवर्तन संभव है। विरोधी सक्रिय रहेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मित्रों की सहायता कर पाएंगे।

वृषभ — व्यवसाय में ध्यान देना पड़ेगा। व्यर्थ समय न गंवाएं। पूजा-पाठ में मन लगेगा। कानूनी अड़चन दूर होगी। जल्दबाजी से हानि संभव है। थकान रहेगी। कुसंगति से बचें।

मिथुन — घर-परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। वाणी पर नियंत्रण रखें। चोट व दुर्घटना से बड़ी हानि हो सकती है। लेन-देन में जल्दबाजी न करें।

कर्क — कानूनी अड़चन दूर होकर लाभ की स्थिति निर्मित होगी। प्रेम-प्रसंग में जोखिम न लें। व्यापार में लाभ होगा। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। निवेश में सोच-समझकर हाथ डालें।

सिंह — बेरोजगारी दूर करने के प्रयास सफल रहेंगे। परीक्षा व साक्षात्कार आदि में सफलता प्राप्त होगी। स्थायी संपत्ति से बड़ा लाभ हो सकता है। समय पर कर्ज चुका पाएंगे।

कन्या — पार्टी व पिकनिक का आनंद मिलेगा। रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे। मनपसंद भोजन का आनंद प्राप्त होगा। व्यापार-व्यवसाय लाभप्रद रहेगा।

तुला — दूर से बुरी खबर मिल सकती है। दौड़धूप अधिक होगी। बेवजह तनाव रहेगा। किसी व्यक्ति से कहासुनी हो सकती है। फालतू बातों पर ध्यान न दें। व्यस्तता रहेगी।

वृश्चिक — कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। चिंता बनी रहेगी। जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा। मेहनत का फल मिलेगा। कार्यसिद्धि होगी।

धनु — उत्साहवर्धक सूचना प्राप्त होगी। भूले-बिसरे साथियों से मुलाकात होगी। विरोधी सक्रिय रहेंगे। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। बड़ा काम करने का मन बनेगा।

मकर — नवीन वस्त्राभूषण की प्राप्ति संभव है। यात्रा लाभदायक रहेगी। बेरोजगारी दूर करने के प्रयास सफल रहेंगे। कारोबारी बड़े सौदे बड़ा लाभ दे सकते हैं। व्यस्तता रहेगी।

कुम्भ — फालतू खर्च पर नियंत्रण रखें। बजट बिगड़ेगा। कर्ज लेना पड़ सकता है। शारीरिक कष्ट से बाधा उत्पन्न होगी। लेन-देन में सावधानी रखें। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

मीन — यात्रा लाभदायक रहेगी। डूबी हुई रकम प्राप्त हो सकती है, प्रयास करें। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। शेयर मार्केट से बड़ा लाभ हो सकता है। संचित कोष में वृद्धि होगी।

भूत बंगला में 26 साल छोटी वामिका गब्बी संग रोमांस करेंगे अक्षय कुमार

फिल्मों में अक्सर हीरो-हीरोइन की ऐसी जोड़ी देखी जाती हैं जहां उम्र का एक बड़ा फासला होता है। एक्टर्स हमेशा इसे नॉर्मल सी बात बताते हैं या स्क्रिप्ट की डिमांड कहकर टाल देते हैं। हाल ही में अक्षय कुमार ने भी इस पर अपनी राय रखी और बताया कि लीड पेयर्स का ऐसा होना आम है। भूत बंगला फिल्म में अक्षय कुमार के ऑपोजिट वामिका गब्बी होंगी। जो उनसे उम्र में 26 साल छोटी हैं।

58 साल के अक्षय फिल्म में 32 साल की वामिका संग रोमांस करते नजर आएंगे। एक बार फिर जब इस एज गैप को लेकर सवाल हुए तो अक्षय ने भी इसे स्क्रिप्ट की डिमांड बता दी। अक्षय कुमार ने कहा,तो क्या हुआ? क्या हमने पहले कभी ऐसा नहीं देखा? हॉलीवुड में भी ऐसा होता है। कई बार ये स्क्रिप्ट की डिमांड होती है। असल जिंदगी में भी लोग अपने से बड़े या छोटे पार्टनर से शादी करते हैं।

फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन का मानना है कि एक्टर्स को उनके किरदार के हिसाब से देखना चाहिए। उन्होंने कहा, एमजीआर और एनटीआर जैसे कलाकार कहते थे कि असली उम्र और स्क्रीन पर दिखने वाली उम्र में फर्क होता है। एक्टर की स्क्रीन एज उसकी असली उम्र से अलग हो सकती है और दर्शक उसे उसी रूप में स्वीकार भी करते हैं। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती।

उन्होंने आगे कहा- जब मैं शूट करता हूं, तो कभी-कभी लगता है कि कोई जोड़ी सही नहीं बैठ रही, लेकिन इसका उम्र से कोई लेना-देना नहीं होता। जब मैं अक्षय या तब्बू के साथ काम करता हूं, तो ऐसा कभी महसूस नहीं होता। और जब दर्शक फिल्म देखते हैं, तो उन्हें भी ये फर्क महसूस नहीं होता।

इसकी वजह है किरदार और उनकी स्क्रीन एज।

अक्षय ने वामिका की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें उनसे उतना ही सीखने को मिला, जितना तब्बू और विद्या बालन जैसी सीनियर एक्टर्स से मिलता है। उन्होंने कहा- मैं वामिका से पहली बार 'भूत बंगला' की शूटिंग के दौरान मिला। उनका काम करने का तरीका अलग है। वो अपने सीन बार-बार पढ़ती हैं और रिहर्सल करती हैं। काफी सीरियस रहती हैं। तब्बू उनसे भी ज्यादा सीरियस हैं। वहीं विद्या, जिनके साथ मैं अनीस बज्मी की फिल्म में काम कर रहा हूं, वो काफी फ्री होकर काम करती हैं।

जल्द ही 'बिलेनियर' में दमदार किरदार निभायेंगे अर्जुन रामपाल

धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है, इस फिल्म की सफलता में अर्जुन रामपाल का भी हाथ है। फिल्म में उन्होंने मेजर इकबाल का खूंखार रोल किया है। अर्जुन रामपाल के अभिनय को खूब सराहा गया। इस फिल्म की सफलता के बीच अर्जुन रामपाल के पास कई नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। जल्द ही वह 'बिलेनियर' नाम की सीरीज में नजर आएंगे। इस सीरीज को लेकर अर्जुन रामपाल भी काफी एक्साइटेड हैं। अर्जुन रामपाल सीरीज 'बिलेनियर' में एक दमदार किरदार करेंगे। इस सीरीज को जाने माने फिल्ममेकर हंसल मेहता और रॉबी ग्रेवाल बनाएंगे।

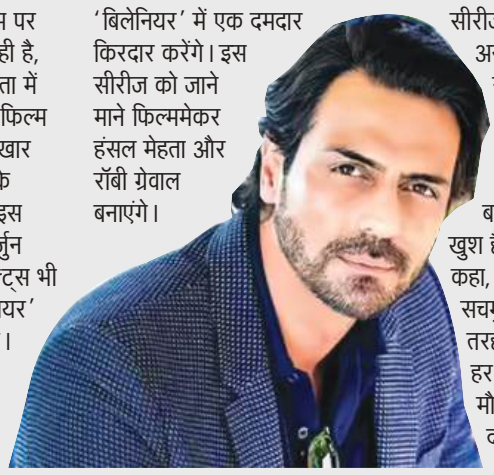

सीरीज 'बिलेनियर' की कहानी अनुभव चोपड़ा और शांतनु सागर ने लिखी है। ऑलमाइटी मोशन पिक्चर के बैनर तले प्रभलीन संधू इसे प्रोड्यूस कर रही हैं।

इस सीरीज का हिस्सा बनकर अर्जुन रामपाल काफी खुश हैं, एक प्रेस नोट में उन्होंने कहा, 'मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर सचमुच बहुत उत्साहित हूं। इस तरह का किरदार निभाने का मौका हर रोज नहीं मिलता, जब ऐसा मौका मिलता है, तो आप उसे दोनों हाथों से लपक लेते हैं। बेहतरीन फिल्ममेकर हंसल मेहता और रॉबी ग्रेवाल के साथ काम करना मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह सपना जल्द ही पूरा होने वाला है।' अर्जुन रामपाल की अपकमिंग सीरीज 'बिलेनियर' अमेजन एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम होगी। इस सीरीज की रिलीज डेट को लेकर अभी कोई अपडेट शेयर नहीं कियागया है। इस सीरीज की कहानी एक ऐसे बिलेनियर की है, जो महत्वाकांक्षी है और सत्ता और सफलता के लिए कुछ भी कर सकता है।

बॉलीवुड | मन की बात

स्मोकिंग सीन को लेकर माधवन ने सिख समुदाय से मांगी माफी

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर 2 का धमाका जारी है एक तरफ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है, तो वहीं, दूसरी तरफ फिल्म को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। फिल्म में आर माधवन के एक सीन पर सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। ऐसे में माधवन ने अब अपने सीन पर चल रहे विवाद पर सफाई दी है और सिख समुदाय से माफी भी मांगी है। माधवन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो मैसेज शेयर किया है। उन्होंने फिल्म को प्यार देने के लिए दर्शकों का शुक्रिया अदा किया और अपने एक स्मोकिंग सीन पर हो रहे विवाद पर सफाई भी दी। माधवन ने स्वीकार किया कि कुछ दर्शक उनके स्मोकिंग सीन से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक गलतफहमी है। उन्होंने सिख समुदाय का अपमान नहीं किया है। वो हर समुदाय की इज्जत करते हैं। माधवन ने वीडियो मैसेज में कहा- धुरंधर के पूरे परिवार की तरफ से आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारी फिल्म को इतना प्यार दिया है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि इस पर हम कैसे रिएक्ट करें। हाल ही में हमें पता चला है कि कुछ लोगों को इस बात से तकलीफ हुई है कि फिल्म के एक सीन में मैंने सिगरेट पीते हुए पवित्र ग्रंथ की लाइनें बोली हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये सही नहीं है। थोड़ी गलतफहमी हुई है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इस सीन के दौरान ये लाइनें बोलने से पहले आदित्य धर जी ने मुझसे कहा था कि ये लाइनें बोलने से पहले ही आप सिगरेट बुझा देना। उन्होंने ये भी कहा था कि आपके मुंह से उस सीन में न धुआं निकलेगा और ना स्क्रीन पर कहीं धुआं दिखाई देगा, ना आपके हाथ में सिगरेट होगी, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत पवित्र है। मैंने सिगरेट बुझा दिया था। आप सीन देखेंगे कि मेरे मुंह से न धुआं निकला है और न सीन में कहीं धुआं दिखा है। उस पूरे सीन में सिगरेट नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम आनजाने में भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते।

सफेद लंबी टोपी क्यों पहनते हैं शेफ? सिर्फ फैशन नहीं, पीछे है खास वजह

जब भी हम किसी पांच सितारा होटल, रेस्टोरेंट या बेकरी में जाते हैं तो शेफ को सफेद कोट के साथ सिर पर लंबी-सी सफेद टोपी पहने देखते है। यह टोपी उनकी पहचान बन चुकी है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सिर्फ फैशन या दिखावे का हिस्सा मानते है। असलियत में इस टोपी के पीछे कई महत्वपूर्ण वजहें हैं जो स्वास्थ्य, सफाई, आराम और किचन की परंपरा से जुड़ी है। आइए जानते हैं इस आइकॉनिक टोपी का पूरा इतिहास और महत्व।

इस टोपी को आधिकारिक तौर पर टोक ब्लांच कहा जाता है। फ्रेंच भाषा में 'टोक' का मतलब है टोपी और 'ब्लांच' का मतलब सफेद। यह नाम 19वीं सदी में प्रचलित हुआ। टोपी की शुरुआत 16वीं-17वीं सदी से मानी जाती है, लेकिन आधुनिक रूप देने का श्रेय प्रसिद्ध फ्रेंच शेफ मारी-आंतोआन कैरम को जाता है। उन्हें 'शेफ ऑफ किंग्स एंड किंग ऑफ शेफ्स' कहा जाता है। कैरम ने फ्रेंच हॉट कुजीन को व्यवस्थित किया और शेफ की यूनिफॉर्म को स्टैंडर्ड बनाया। उन्होंने सफेद रंग को चुना क्योंकि यह सफाई और शुद्धता का प्रतीक है।

स्वास्थ्य और सफाई: सबसे महत्वपूर्ण कारण बाल खाने में गिरने से रोकना है। लंबी ड्रेसिंग के दौरान शेफ के सिर से बाल या रूसी गिर सकती है, जो खाने को दूषित कर सकती है। टोपी बालों को पूरी तरह कवर करती है। साथ ही सफेद रंग किसी भी दाग-धब्बे को तुरंत दिखा देता है, जिससे शेफ को फौरन सफाई करने की याद आती है। गहरे रंग की टोपी में दाग छिप जाते हैं, लेकिन सफेद रंग सफाई बनाए रखने के लिए मजबूर करता है।

पसीना सोखना और ठंडक बनाए रखना: किचन में तापमान बहुत ज्यादा होता है- चूल्हे, ओवन और गर्म तेल की वजह से। टोपी के अंदर हवा का सर्कुलेशन होता है जो सिर को ठंडा रखता है। लंबी टोपी पसीने को सोखती है और माथे से पसीना खाने में गिरने से बचाती है।

किचन में रैंक और पदानुक्रम: पुराने समय में टोपी की ऊंचाई शेफ के अनुभव और पद को दर्शाती थी। हेड शेफ सबसे लंबी टोपी पहनते थे, जबकि जूनियर शेफ छोटी। कुछ कहानियों में कहा जाता है कि टोपी में 100 प्लेट्स (चुनट) अंडे पकाने की 100 अलग-अलग विधियों का प्रतीक होती थी। हालांकि आजकल यह ज्यादा प्रतीकात्मक है।

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व: कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसकी जड़ें प्राचीन असिरियन साम्राज्य या बाइजेंटाइन साम्राज्य तक जाती हैं, जहां रसोइये राजा की तरह टोपी पहनते थे ताकि उनकी इज्जत बनी रहे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय शेफ राजपरिवार से जुड़े होने के कारण खतरे में थे, इसलिए उन्होंने भी विशिष्ट टोपी अपनाई।

अजब-गजब | इस जनजाति को जाता है दुनिया का आखिरी नरभक्षी

पेड़ों पर रहते हैं ये आदिवासी, होते हैं नरभक्षी और अंधविश्वासी, महिलाएं जीती हैं नर्क जैसी जिंदगी!

आधुनिकता की दौड़ में दुनिया मंगल ग्रह पर पहुंचने की तैयारी कर रही है, लेकिन धरती पर आज भी कुछ ऐसे कोने मौजूद हैं जहां समय सदियों पहले ही रुक गया है। इंडोनेशिया के पापुआ प्रांत के बेहद घने और दलदली जंगलों के बीच रहने वाली कोरोवाई जनजाति एक ऐसी ही दुनिया का हिस्सा है। इन लोगों को दुनिया के आखिरी नरभक्षी के तौर पर जाना जाता है। लगभग 3,000 की आबादी वाली यह जनजाति अपनी अनोखी जीवनशैली और खौफनाक मान्यताओं के कारण हमेशा चर्चा में रहती है। कोरोवाई लोगों के बारे में बाहरी दुनिया को पहली बार 1974 में तब पता चला, जब एक डच मिशनरी ने अनजाने में इनकी खोज की थी। इससे पहले ये लोग पूरी तरह दुनिया से कटे हुए थे और इन्हें यह भी नहीं पता था कि जंगल के बाहर कोई इंसानी बस्ती मौजूद है।

कोरोवाई जनजाति की सबसे बड़ी खासियत उनके घर हैं, जिन्हें रूमा टिंगी कहा जाता है। ये लोग जमीन पर नहीं बल्कि 40 से 100 फीट की ऊंचाई पर पेड़ों की चोटियों पर अपने घर बनाते हैं। इतनी ऊंचाई पर घर बनाने के पीछे कई कारण हैं, एक तो जंगली जानवरों और मच्छरों से बचाव, दूसरा बाढ़ से सुरक्षा और सबसे अहम कारण है बुरी आत्माओं का डर। कोरोवाई लोगों का मानना

है कि रात में जंगल में बुरी आत्माएं घूमती हैं और उनसे बचने के लिए ऊंचाई पर रहना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। ये घर लकड़ी, बांस और पत्तों से बनाए जाते हैं और इनमें जाने के लिए लकड़ी के तने पर खांचे बनाकर सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। नरभक्षण को लेकर कोरोवाई जनजाति की मान्यताएं बेहद हैरान करने वाली हैं। ये लोग किसी भी इंसान को नहीं मारते, बल्कि ये सिर्फ खाखुआ को मारते हैं।

इस जनजाति के लोगों की मान्यता है कि खाखुआ एक डायन या बुरी आत्मा होती है, जो इंसान के शरीर में घुसकर उसे अंदर से खाना शुरू कर देती है। जब कोई व्यक्ति बीमार होकर मरने वाला होता है, तो वह उस व्यक्ति का नाम लेता है, जिसे वह खाखुआ मानता है। व्यक्ति की मौत के बाद कबीले के लोग उस कथित खाखुआ को पकड़ते हैं, उसे मारते हैं और फिर उसका मांस खा जाते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से वे बुरी आत्मा का खात्मा कर रहे हैं। हालांकि, पिछले कुछ दशकों में बाहरी संपर्क और सरकार की सख्ती के बाद यह प्रथा लगभग खत्म हो चुकी है। कोरोवाई समाज में महिलाओं की स्थिति आज भी बेहद चुनौतीपूर्ण है। यहां का समाज पूरी तरह से पुरुष प्रधान है। महिलाओं का मुख्य काम सिर्फ बच्चे पैदा करना, घर संभालना और सागो के पेड़ों से स्टार्च निकालकर खाना तैयार करना है।

पुरुषों के लिए खाने के लिए शिकार करना और रहने के लिए घर बनाना मुख्य कार्य है, जबकि महिलाएं दिन भर कड़ी मेहनत करती हैं। पुरुषों और महिलाओं के रहने के कमरे भी अक्सर अलग-अलग होते हैं। यहां बहुविवाह की प्रथा भी प्रचलित है और कई बार महिलाओं को कड़ी शारीरिक सजाओं का सामना भी करना पड़ता है। 90 के दशक में जब बाहरी दुनिया से संपर्क बढ़ा, तो इस क्षेत्र में पर्यटन और मिशनरी गतिविधियों के साथ-साथ वेश्यावृत्ति जैसी समस्याएं भी पनपने लगी थीं। लेकिन 1999 के आसपास इंडोनेशियाई सरकार ने कड़े कदम उठाए और इन गतिविधियों पर लगाम लगाई।

सरकार-विपक्ष के बीच छिड़ी तीखी बहस

» पश्चिम एशिया संकट पर हुई सर्वदलीय बैठक रही हंगामेदार

» लोस और रास में पश्चिम एशिया संकट को लेकर चर्चा हो

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। मिडल ईस्ट में जारी तनाव और युद्ध की स्थिति पर चर्चा करने के लिए संसद परिसर में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक हंगामेदार रही। एक ओर जहां सरकार ने भारत के रुख को स्पष्ट करते हुए पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला, वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार की विदेश नीति को असंतोषजनक करार दिया। बैठक में सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर हुई बातचीत में पश्चिम एशिया के युद्ध को तुरंत समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि इस युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था और मानवता को नुकसान हो रहा है, इसलिए इसे जल्द खत्म होना चाहिए।

सूत्रों के अनुसार, सरकार ने विपक्ष के इस आरोप का खंडन किया कि भारत सरकार इस मामले पर चुप है और कहा कि ''हम टिप्पणी कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं।'' सरकार का पक्ष था कि जब ईरान दूतावास खोला गया, तो विदेश सचिव ने तुरंत वहां दौरा किया और शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के मारे जाने पर जल्द शोक व्यक्त न करके नैतिक कमजोरी दिखाई है। विपक्ष ने कहा कि इस मामले से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सरकार का जवाब संतोषजनक नहीं था। उन्होंने यह मांग फिर दोहराई कि लोकसभा में नियम 193 और राज्यसभा में नियम 176 के तहत पश्चिम एशिया संकट को लेकर चर्चा होनी चाहिए। सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने संवाददाताओं से कहा, ''सरकार की ओर से स्पष्टीकरण देने की कोशिश हुई जो संतोषजनक नहीं है। हम लोगों की मांग है कि लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद लोगों को संतुष्टि होगी। उनका कहना था कि बहुत सारे मुद्दे थे, जिन पर सरकार का जवाब संतोषजनक नहीं था। उन्होंने यह भी कहा, ''पाकिस्तान जो हमसे हर तरह से कमजोर है, वो मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और हम मूकदर्शक बने हुए हैं।

विपक्ष ने सरकार की विदेश नीति को असंतोषजनक करार दिया

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक

संसद भवन परिसर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू शामिल हुए। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर एवं मुकुल वासनिक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शप) की नेता सुप्रिया सुले, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, राजद के अभय सिन्हा और कई अन्य नेता शामिल हुए। तृणमूल कांग्रेस इस बैठक में शामिल नहीं हुई।

पाक पर दलाल राष्ट्र का तंज

बैठक का सबसे चर्चित हिस्सा वह रहा जब सरकार ने पाकिस्तान के मध्यस्थता के प्रयासों को सिरे से खारिज कर दिया। सूत्रों के मुताबिक, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान का अमेरिका द्वारा 1981 से केवल इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान को दलाल राष्ट्र करार देते हुए सरकार ने कहा कि हम दलाल राष्ट्र नहीं हैं। हमारे प्रयास ठोस और स्वतंत्र हैं। यह बयान विपक्ष के उस आरोप के जवाब में आया जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान जैसा कमजोर देश मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है जबकि भारत मूकदर्शक बना हुआ है।

नियम 193 और 176 के तहत चर्चा जरूरी : धर्मेंद्र

समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि लोकसभा में नियम 193 और राज्यसभा में नियम 176 के तहत चर्चा जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष की ओर से किए गए बहुत सारे सवालों का जवाब संतोषजनक नहीं था।

केंद्र सरकार ट्रंप से नहीं विपक्ष से करे बात : राउत

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश नीति संबंधी दृष्टिकोण की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं के बजाय घरेलू राजनीतिक परामर्श पर अधिक ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच हाल ही में हुई फोन कॉल पर टिप्पणी करते हुए यूबीटी सांसद ने कहा कि मध्य पूर्व संकट जैसे वैश्विक मुद्दों पर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करने के बजाय मोदी को भारत में विपक्ष से बात करनी चाहिए, जिससे बेहतर परिणाम मिलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप ऐसे व्यवहार कर रहे हैं मानो वे मोदी के बॉस हों। संजय राउत ने कहा कि ट्रम्प से बात करने के बजाय, मोदी को देश के विपक्ष से बात करनी चाहिए; उन्हें उनसे बेहतर सुझाव मिलेंगे। ट्रम्प तो मोदी के बॉस जैसे हैं। राउत ने मौजूदा वैश्विक संघर्षों में भारत की भूमिका पर सवाल उठाते हुए पाकिस्तान की कूटनीतिक स्थिति का जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान ने ट्रंप के साथ बातचीत में समझौता करने की इच्छा दिखाई है, जिसकी सराहना की जा रही है।

गायकवाड़ के साथ संजू सैमसन करेंगे ओपनिंग

» आयुष की लेंगे जगह, अब म्हात्रे नंबर तीन पर या फिर टीम से हो सकते हैं बाहर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी बल्लेबाजी क्रम में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने साफ किया कि आयुष म्हात्रे इस बार ओपनिंग नहीं करेंगे। उनकी जगह टीम इंडिया के स्टार संजू सैमसन उनके साथ पारी की शुरुआत करेंगे। यानी इस सीजन ऋ तुराज के साथ संजू सैमसन ओपनिंग करेंगे। क्योंकि पिछले सीजन टीम ने आयुष म्हात्रे पर भरोसा जताया था।

ओपनिंग से हटने के बाद अब आयुष म्हात्रे को इस सीजन बेंच पर बैठना पड़ सकता है या फिर सीएसके उन्हें नंबर तीन पर उतार सकता है। हालांकि, नंबर तीन पर म्हात्रे के खेलने की संभावना बेहद कम है। टीम मैनेजमेंट इस पोजिशन पर एक विस्फोटक बल्लेबाज का इस्तेमाल कर संतुलन बनाना चाहती है। ऐसे में सरफराज खान या फिर उर्विल पटेल में से किसी एक को मौका मिल सकता है। वहीं, शिवम दुबे (नंबर चार पर) और दक्षिण अफ्रीका के युवा स्टार डेवाल्ड ब्रेविस मिडिल ऑर्डर (नंबर पांच पर) में अपनी जगह बनाए रखेंगे। छठे नंबर पर 14.2 करोड़ के प्रशांत वीर हो सकते हैं। वहीं, 14.2 करोड़ के ही नए स्टार कार्तिक शर्मा बल्लेबाजी में इम्पैक्ट प्लेयर बन सकते हैं। धोनी को सातवें या फिर आठवें पर स्थिति के हिसाब से भेजा जा सकता है। ऐसे में चेन्नई की बैटिंग ऑर्डर विस्फोटक दिख रही है। गेंदबाजी में नूर अहमद, मैट हेनरी, अंशुल कंबोज और खलील अहमद खेल सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स अपना पहला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 30 मार्च को शाम साढ़े सात बजे से खेलेगी।

आईसीसी टी20 रैंकिंग में कीवी गेंदबाजों ने लगाई छलांग

नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन के साथ पुरुषों की आईसीसी टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों को फायदा मिला है। इस लिस्ट में चार कीवी तेज गेंदबाजों ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। लॉकी फर्ग्यूसन 12 पायदान ऊपर चढ़कर 39वें स्थान पर पहुंचा दिया है। उनके साथी बेन सियर्स 20 पायदान ऊपर चढ़कर 59वें स्थान पर पहुंच गए हैं। काइल जैमीसन ने पांच पायदान की छलांग लगाई है। वह 76वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं, जैकरी फॉल्क्स आठ पायदान ऊपर चढ़कर 81वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं भारत के अभिषेक शर्मा टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं। वह फिलहाल हमवतन ईशान किशन से आगे चल रहे हैं। हालांकि, भारत की टी20 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव दो पायदान ऊपर चढ़कर सातवें स्थान पर पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज टिम रॉबिन्सन उन चुनिंदा बल्लेबाजों में से एक रहे जिन्होंने रैंकिंग में सुधार किया। वेलिंगटन में 32 रनों की पारी खेलने के बाद वह दो पायदान ऊपर चढ़कर 34वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

आंध्र प्रदेश बस हादसे में 14 की मौत

» पीएम व सीएम ने जताया शोक, आर्थिक मदद देने का किया एलान

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के मार्कपुरम में बस-टिपर टक्कर के बाद लगी आग में 14 लोगों की मौत हो गई और 15 घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को दो लाख और घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता देने की घोषणा की।यह दर्दनाक हादसा मार्कपुरम जिले के रायवरम के पास सुबह करीब 6:30 बजे हुआ।

हरीकृष्ण ट्रेवल्स की यात्री बस हैदराबाद से पामुरु (प्रकाशम जिला) की ओर जा रही थी, तभी एक पत्थर की खदान के पास उसकी टिपर ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन पूरी तरह से आग की लपटों में घिर गए। बस में उस समय 35 यात्री सवार थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को मार्कपुरम के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। मृतकों और घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग लगने के तुरंत बाद करीब दस यात्री बस से कूदने में सफल रहे।

अविमुक्तेश्वरानंद को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यौन शोषण के मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी को बुधवार को अग्रिम जमानत दे दी। हालांकि अदालत ने शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ताओं दोनों को इस संबंध में मीडिया के समक्ष कोई बयान नहीं देने का निर्देश दिया।

इससे पूर्व, अदालत ने 27 फरवरी को अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। अग्रिम जमानत देते हुए अदालत ने याचिकाकर्ताओं पर कई शर्तें लगाईं जैसे कि वे साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेंगे औरसुनवाई की तिथि पर संबंधित अदालत के समक्ष पेश होंगे। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को तथ्य छिपाने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई लालच, धमकी नहीं देंगे और संबंधित अदालत की पूर्व अनुमति के बगैर विदेश नहीं जाएंगे।

भजन लाल 'नॉन-रेसिडेंट सीएम': जूली

» सीएम की पीएम से मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

जयपुर। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सीएम भजनलाल के दिल्ली दौरे को लेकर कहा- आज राजस्थान एक गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है, लेकिन सीएम जनता की पीड़ा समझने के बजाय नॉन-रेसिडेंट मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। बता दें भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। नवरात्रि के पावन अवसर पर हुए इस दौरे के दौरान उनकी मुलाकात संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चंदन की लकड़ी से बनी मां दुर्गा की प्रतिमा भेंट कर सांस्कृतिक जुड़ाव का संदेश भी दिया।

इस मुलाकात के बाद राजस्थान की राजनीति में संभावित फैसलों और नए समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। जूली ने कहा कि राजस्थान की चिकित्सा और व्यवस्था लगभग ढह चुकी है, जनता का जीवन खतरे में है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का एक पैर हमेशा दिल्ली में ही रहता है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री को कॉन्फिडेंट होकर नेतृत्व करना चाहिए था और स्वास्थ्य मंत्री को इस संकट को सुलझाने के लिए निर्देश देने चाहिए थे। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के विजन की याद दिलाते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जो लोग तुलना की बात करते हैं, उन्हें एक बार अस्पतालों की जमीनी हकीकत देख लेनी चाहिए।

मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर अटकलें भी तेज

दिल्ली दौरे के बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर अटकलें भी तेज हो गई हैं। हालांकि, आधिकारिक तौर पर इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला सहित कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की, जिससे इस दौरे की राजनीतिक अहमियत और बढ़ गई है।

ट्रंप की साख हुई राख, 27 वें दिन भी बमबारी

अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा- युद्ध रोकने को लेकर बातचीत जारी, ईरान की ओर से संघर्ष विराम से इनकार

» शांति बहाली के कोशिश में उपराष्ट्रपति वेंस

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। ईरान से छिड़ी जंग अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहीं है। ये लड़ाई अब 27वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया है कि तेहरान के शीर्ष नेतृत्व के साथ युद्ध रोकने को लेकर बातचीत जारी है।

हालांकि, ईरान की ओर से संघर्ष विराम को लेकर बातचीत से इनकार किया गया है। युद्ध रोकने के दावों और इनकार की इस हुज्जत में ट्रंप की इज्जत दांव पर लग गई है। वहीं, कई अंतराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान और अमेरिका-इस्त्राइल के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए कूटनीतिक कोशिशें तेज कर दी गई हैं। इसे आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शांति वार्ता करने जा सकते हैं।

ईरान ने क्षेत्रीय देशों को दी सख्त चेतावनी

ईरान ने क्षेत्रीय देशों को सख्त चेतावनी दी है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालिबाफ ने कहा कि अगर कोई भी क्षेत्रीय देश ईरान के दुश्मनों के साथ मिलकर ईरान के किसी द्वीप पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो उसकी महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर बिना किसी सीमा के निशाने पर होगी। कालिबाफ ने अरबी भाषा में एक्स पर लिखा, कुछ जानकारी के अनुसार, ईरान के दुश्मन एक क्षेत्रीय देश की मदद से हमारे एक द्वीप पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे सशस्त्र बल हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। अगर कोई कदम उठाया गया तो उस क्षेत्रीय देश की सारी महत्वपूर्ण सुविधाएं बिना रुके और बिना किसी सीमा के हमारा निशाना बनेंगी।

ईरान को अमेरिका के अधिकारियों पर भरोसा नहीं

ईरानी अधिकारियों ने साफ किया कि पिछली बार इन नेताओं के साथ बातचीत के कुछ ही समय बाद तेहरान पर सैन्य हमले शुरू हो गए थे। ईरान की ओर से इन अधिकारियों पर भरोसा नहीं जताया गया है। वहीं, जेडी वेंस पहले से ही मध्य पूर्व के संघर्षों में अमेरिका के उलझने के खिलाफ साफ रुख अपनाते रहे हैं। ईरान का मानना है कि जेडी वेंस इस युद्ध को जल्द खत्म कराने में व्यावहारिक और अहम भूमिका निभा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की ओर से इस संभावित बैठक में संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबाफ वार्ता का नेतृत्व कर सकते हैं।

पाकिस्तान जा सकते हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस

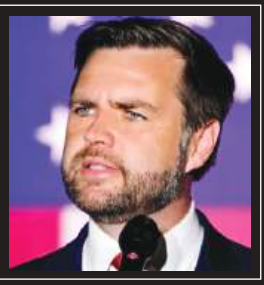

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस सप्ताह के अंत तक पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं, ताकि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किए गए युद्ध को खत्म करने का रास्ता निकालने पर चर्चा की जा सके। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई है। दरअसल खबरें आईं कि ईरान के प्रतिनिधियों ने ट्रंप सरकार से कहा कि वे दूत स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर के साथ फिर से बातचीत शुरू नहीं करना चाहते। इसके बाद इस्लामाबाद ने जेडी वेंस का नाम आगे बढ़ाया है। हालांकि इस बीच व्हाइट हाउस ने कहा है कि उपराष्ट्रपति की भूमिका बातचीत में ज्यादा सक्रि य होने वाली नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने को कहामुझे नहीं लगता कि कुछ भी बदला है।

ईरान ने 70 से ज्यादा इजरायली ठिकानों पर प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलें दागीं

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस (आईआरजीसी) ने जवाबी कार्रवाई का नया रिकॉर्ड बनाया है। आईआरजीसी ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 81वीं लहर में 70 से ज्यादा इजरायली ठिकानों पर प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलें दागीं। पब्लिक रिलेशंस विभाग ने बयान जारी कर कहा कि एमाद, कियाम, खोर्रमशहर-4 और कद्र मिसाइलों से हाइफा, दिमोना, हाइफा के पास अल-खुद्रिय्या और तेल अवीव के उत्तर व दक्षिण इलाकों को निशाना बनाया गया। आईआरजीसी का दावा है कि पिछले तीन हमलों के बाद इजरायल के हताहतों की संख्या अब 2,500 से ज्यादा हो चुकी है।

ट्रंप सलाहकारों से बोले- समाधान खोजें!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जंग खत्म करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने शीर्ष सलाहकारों को निर्देश दिया है। ट्रंप ने कहा है कि किसी भी हाल में कुछ हफ्तों के भीतर सैन्य संघर्ष को खत्म करने का रास्ता निकालें। ट्रंप अब इस लंबी खिंचती लड़ाई को और खींचने के मूड में नहीं हैं। सूत्रों के मुताबिक, ट्रंप अब इस लंबी खिंचती लड़ाई को और खींचने के मूड में नहीं हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रैंड डील के जरिए इस अध्याय को बंद करना चाहते हैं।

अमेरिका-इजरायल ने शिराज में मिसाइल बेस को बनाया निशाना

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान के दक्षिणी शहर शिराज में एक बड़े मिसाइल बेस को निशाना बनाकर एयरस्ट्राइक किए जाने की खबर सामने आई है। एक अमेरिकी थिंक टैंक/संस्थान के अनुसार, इन हमलों में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्य क्र म से जुड़े ठिकानों को टारगेट किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह बेस ईरान के प्रमुख मिसाइल इन्फ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा माना जाता है, जहां मिसाइलों का निर्माण, भंडारण या संचालन किया जाता था। पहले भी इस क्षेत्र में ऐसे सैन्य ठिकानों पर हमले की पुष्टि हो चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के हमलों का मकसद ईरान की मिसाइल क्षमताओं को कमजोर करना और क्षेत्र में उसकी सैन्य ताकत को सीमित करना है। हालांकि, हमले से हुए नुकसान और हताहतों को लेकर आधिकारिक तौर पर अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है।

खार्ग द्वीप की ट्रंप की कब्जे वाली रणनीति से भड़का तेहरान

ईरान ने अपने सबसे अहम खार्ग द्वीप को एक अभेद्य किले में तब्दील करना शुरू कर दिया है। यह वही द्वीप है जिसे कब्जाने की योजना ट्रम्प प्रशासन बना रहा है। ईरान ने यहां न केवल भारी तादाद में अतिरिक्त सैन्य बल तैनात किए हैं, बल्कि अमेरिकी सैनिकों के लिए घातक जाल भी बिछाए हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों के हवाले से जानकारी मिली है कि ट्रंप प्रशासन इस छोटे से द्वीप पर जमीनी कार्रवाई करने और इसे अपने नियंत्रण में लेने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। खार्ग द्वीप ईरान के लिए किसी गोल्डन डक से कम नहीं है, क्योंकि ईरान के कुल कच्चे तेल के निर्यात का लगभग 90प्रतिशत हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। अमेरिका का मानना है कि इस द्वीप को कब्जे में लेकर वह ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से खोलने के लिए मजबूर कर सकता है और इसे सौदेबाजी के लिए एक बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है।

ईरान ने बिछाया बारूदी सुरंगों का जाल

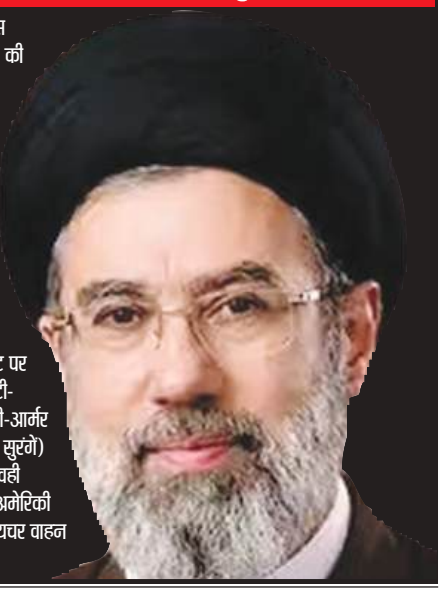

अमेरिका की इस संभावित योजना की भनक लगते ही ईरान ने खार्ग द्वीप की सुरक्षा को कई परतों में बांट दिया है। सूत्रों का कहना है कि ईरानी सेना ने द्वीप के चारों ओर और विशेष रूप से समुद्र तट पर भारी मात्रा में एंटी-पर्सनल और एंटी-आर्मर माइन्स (बारूदी सुरंगें) बिछा दी हैं। यह वही इलाका है जहां अमेरिकी सेना अपने उभयचर वाहन उतार सकती है।

महाराष्ट्र कार्यालय:- 2 जी, कृष्णा कुटीर सागरिका CHS जुहू तारा रोड जुहू- मुंबई- 400049। विधि सलाहकार: मोहम्मद हैदर
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
RNI-UPHIN/2015/62233, दूरभाष: 0522- 4078371 | Email: daily4pm@gmail.com | website: www.4pm.co.in |
समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।

स्वामी 4 पीएम न्यूज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए
मुद्रक एवं प्रकाशक संजय शर्मा
द्वारा आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित
पता 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। संपादक- संजय शर्मा